Fiscal Policy & its objectives
राजकोषिय नीति एवं इनके उद्देश्य

Classical economist के अनुसार बचत का बजट ही उचित होती है। उस समय स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था का विशेष महत्व था और सरकारी हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया गया था।

1930 की विश्वव्यापी मंदी के समय राजकोषिय नीति में परिवर्तन आने लगा। इस नीति का उपयोग आर्थिक स्थिरता, कीमत नियन्त्रण, बेरोजगारी को दूर करने तथा आर्थिक विकास के लिए किया जाने लगा। अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च उद्देश्यों की प्राप्ती के लिए राजकोषिय नीति व्यय, ऋण, कर, आय, हीनार्थ प्रबन्ध आदि की समुचित व्यवस्था करती है।

Classical economists के अनुसार अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार रहता है, कभी भी आति-उत्पादन की समस्या नहीं होती है। लेकिन विश्वव्यापी मंदी के बाद राजकोषिय नीति का उपयोग बेरोजगारी व आति-उत्पादन की समस्या दूर करने के लिए, उच्च रोजगार, कीमत में स्थिरता, विदेशी व्यापार में संतुलन एवं आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए किया जाने लगा। राजकोषिय नीति के निम्नलिखित उद्देश्य है —

1. Fiscal Policy and Employment

विश्वव्यापी मंदी के बाद Keynes ने रोजगार का सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिसे प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धान्त भी कहते है। Keynes के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग से बातों पर निर्भर करता है उपभोग एवं विनियोग। उपभोग को Keynes ने दीर्घकाल में स्थिर माना। लेकिन विनियोग तो बातों पर निर्भर करती है MEC और Rate

Scanned with CamScanner

of Interest | MEC भी दीर्घकाल में स्थिर होती है। क्योंकि ये मनोविज्ञान पर निर्भर करते हैं। अंत में ब्याज दर ही विनियोग को प्रभावित करता है। ब्याज की दर में कमी लाकर विनियोग को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ब्याज दर में कमी के समय अगर निवेशकर्ता को सम्भावित लाभ में कमी होने का एहसास हो तो वह कितना भी ब्याज दर कम किया जाय निवेश नहीं बढ़ेगा। तब सरकारी व्यय ही एकमात्र विकल्प होता है जिससे बेरोजगारी दूर किया जाए। सार्वजनिक निर्माण कार्य के द्वारा सरकार बेरोजगारी दूर कर सकती है। इसप्रकार राजकोषिय नीति के भिन्न उपायों द्वारा रोजगार प्राप्त किया जा सकता है।

ⓐ उपभोग प्रवृति बढ़ाने के उपाय

To Increase Propensity to Consume

केन्स के अनुसार धनियों की अपेक्षा निर्धनों की उपभोग प्रवृति अधिक होती है। अतः उनकी आय में वृद्धि की जानी चाहिए। यह तभी सम्भव है जब धनियों पर उस सीमा तक करारोपण किया जाय जहाँ तक उनकी काम करने व बचत करने की इच्छा या योग्यता पर बुरा प्रभाव न पड़े तथा उस आय को निर्धनों की ओर इसप्रकार हस्तान्तरित किया जाय कि उसका प्रत्यक्ष लाभ निर्धनों को मिले।

ⓑ निवेश में वृद्धि (To increase Investment)

निवेश दो प्रकार का होता है व्यक्तिगत एवं सरकारी निवेश व्यक्तिगत निवेश बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयासों से विनियोग के लिए उद्यमियों को आकर्षित करना और स्वदेश में विदेशी पूंजीपतियों को आमंत्रित करके

2. Fiscal Policy and Economic Growth

आर्थिक विकास की समस्या विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में अधिक होती है। अतः राजकोषिय नीति के द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा जा सकता है। ये नितियाँ निम्नलिखित है।

ⓐ राष्ट्रीय आय में वृद्धि (Increase in National Income)

विकासशील देशों में प्रतिव्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय दोनों का ही स्तर काफी कम होता है। आय स्तर को बढ़ाने के लिए राजकोषिय नीति निम्न प्रकार से सहायक होती है—

1. Effective tax System

प्रभावशाली कर प्रणाली के द्वारा आय प्राप्त करके उस आय को सामाजिक कल्याण के कार्यों में व्यय किया जाना चाहिए। जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी।

2. Effective Economic Policies

उचित आर्थिक नीतियों का संचालन इसप्रकार होना चाहिए कि विनियोग कर्ताओं को नये नये विनियोगों की ओर आकर्षित किया जा सके तथा आयात व निर्यात नीति को लोचपूर्ण बनाकर नये उद्योगपतियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए आकर्षित किया जा सके।

3. Increase in Effective Demand

~~उचित आर्थिक नीतियों का संचालन~~ सार्वजनिक ऋण एवं व्ययों को ऐसी दिशा दी जानी चाहिए जिससे Effective demand में वृद्धि हो सके।

4. To maintain ability and Desire of working capacity

राजकोषिय नीति का उद्देश्य इसप्रकार से निर्धारित किया जाय कि लोगों की बचत करने व काम करने की योग्यता पर बुरा प्रभाव न पड़े।

Scanned with CamScanner

निवेश व उत्पादन के स्तर में वृद्धि करना।
सरकारी निवेश को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से ऐसी योजनाओं पर निवेश होगा जो रोजगार मूलक तथा दीर्घकाल तक चलनेवाली होगी जैसे - नदी-घाटी योजना, रेल-सड़क यातायात, पुल आदि। सरकारी निवेश मुख्य रूप से उस समय ज्यादा जरूरी हो जाता है जब मंदी के समय उद्योगपतियों को हानि होती है जिससे वे उत्पादन नहीं बढ़ा पाते।

(c) घाटे का व्यय (Deficit Finance)

जब सरकारी ऋण एवं करारोपण से उपभोग में कमी आने लगती है तो सरकार अपने व्यय को घाटे की वित्त व्यवस्था से भी पूरी कर सकती है। यदि सरकार नोट छापकर व्यय करती है तो इस क्रिया से भी रोजगार में वृद्धि होगी।

(d) व्यय के बिना घाटा (expenditure Without Deficit)

कभी कभी सरकार व्यय में वृद्धि किये बिना effective demand में वृद्धि करके रोजगार में वृद्धि कर सकती है। इसके लिए सरकार कर की दरों में कमी करके लोगों की आय में वृद्धि कर सकती है। जिससे उपभोग एवं रोजगार में वृद्धि होगी।

(e) घाटे के बिना व्यय (Deficit Without expenditure)

बिना घाटे के व्यय में वृद्धि करना "सन्तुलित बजट गुणक" कहलाता है। इस नीति के अन्तर्गत सरकारी व्यय में उतनी ही वृद्धि की जाती है जितनी कि करों की राशि में वृद्धि की गई है। सरकार करारोपण से प्राप्त सम्पूर्ण आय को व्यय कर देती है।

Scanned with CamScanner

(b). Capital Formation

किसी भी देश के आर्थिक विकास में पूँजी निर्माण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। राजकोषिय नीति को प्रभावी बनाकर पूँजी निर्माण में वृद्धि की जा सकती है। सरकारी व्यय एंव करों में वृद्धि करके उपभोग में कमी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त हितार्थ प्रबन्ध, ऋण, विदेशी बचत, बीमा कम्पनी आदि द्वारा भी पूँजी निर्माण में वृद्धि किया जा सकता है।

(c) Justified Equal Distribution

वर्तमान समय में राजकोषिय नीति के द्वारा आय की असमानता को दूर करने का प्रयत्न किये जाते है। सरकार द्वारा सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि करके रोजगार के अवसर को बढ़ाये जाते है। प्रगतिशील करारोपण के द्वारा फिजूलखर्ची को रोका जा सकता है। तथा निर्धनों के आय स्तर को ऊँचा किया जाता है।

(d) Give Employment

राजकोषिय नीति का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी दूर करना होता है। इसलिए सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए ताकि निजी एंव सार्वजनिक निवेशों में वृद्धि की जा सके। इसके लिए उपभोग प्रवृति में वृद्धि कर प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना होता है। ताकि लोगों की माँग का प्रभाव वस्तुओं की बिक्री पर पड़ सके। इस क्रिया के जारी रहने से रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होती है।

(e) To Remove Inflationary Effect

घाटे की वित्त व्यवस्था के द्वारा अतिरिक्त साधनों

Scanned with CamScanner

को चुकाया जाता है। यदि घाटे की पूर्ति करारोपण या ऋण से की जाए तो मुद्रा प्रसार की सम्भावना बहुत कम होती है। परन्तु जब सरकार अपने घाटे की पूर्ति के लिए हिनार्थ प्रबन्ध करती है तो मुद्रा प्रसार बढ़ता है। अतः राजकोषिय ~~नीति~~ नीति के द्वारा मुद्रा प्रसार रोका जा सकता है। इसके लिए करारोपण व ऋण के द्वारा लोगों की अतिरिक्त क्रयशक्ति को छीन लिया जाता है। इस क्रिया से लोगों के द्वारा जितनी अतिरिक्त मुद्रा चलन में आती है उतनी ही मुद्रा लोगों की जेब से कर के द्वारा निकाल ली जाती है जिससे मुद्रास्फीति नहीं होता।

परन्तु हीनार्थ प्रबन्ध से पुरानी मुद्रा की मात्रा में नयी मुद्रा की मात्रा मिल जाने से मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाता है। मुद्रा का चलन-वेग व मुद्रा की मात्रा जिस अनुपात में बढ़ायी जाती है उस अनुपात में वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ पाता है जिससे मुद्रा प्रसार बढ़ता है।

मुद्रा प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए निम्न उपाय किये जाते हैं -

(1) मुद्रा प्रसार के समय अतिरिक्त क्रयशक्ति ~~बढ़ने~~ ~~लोगों की फिजूलखर्ची को रोका जाना चाहिए।~~ पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए।

(2) प्रगतिशील कर ~~के~~ पर करारोपण करके लोगों की फिजूलखर्ची को रोका जाना चाहिए।

(3) अनिवार्य बचतों को प्रोत्साहित एवं ऐच्छिक बचतों के लिए लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए।

Scanned with CamScanner

④ मुद्रा प्रसार को रोकने हेतु वस्तु-कर तथा विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाना चाहिए।

⑤ सरकार को मुद्रा-प्रसार रोकने के लिए प्रगामी कर व्यवस्था को अपनाना चाहिए।

इसप्रकार राजकोषिय नीति के द्वारा रोजगार, आर्थिक विकास तथा कीमत में स्थिरता लाई जा सकती है।

Dr Sandhya Rai
Maharaja College

Scanned with CamScanner